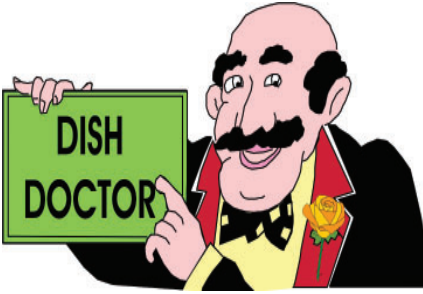


## DISH DOCTOR



*Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.*

*Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3<sup>rd</sup> Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or*

*Email: [manoj.madhavan@nm-india.com](mailto:manoj.madhavan@nm-india.com). Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956*

### DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION (DTT)

**Q:** How is Digital Terrestrial Television (DTT) and the Emergence of Direct-to-Mobile (D2M) going to change the dynamics of the broadcast ecosystem??

*Krishnan Iyer,  
Broadcast Consultant, Chennai*

**Ans.:** Digital Terrestrial Television (DTT) emerged as a more efficient and flexible platform. More recently, a homegrown innovation—Direct-to-Mobile (D2M)—has gained attention. D2M allows smartphone users to watch live TV channels and content without relying on mobile data or internet connectivity, eliminating buffering issues.

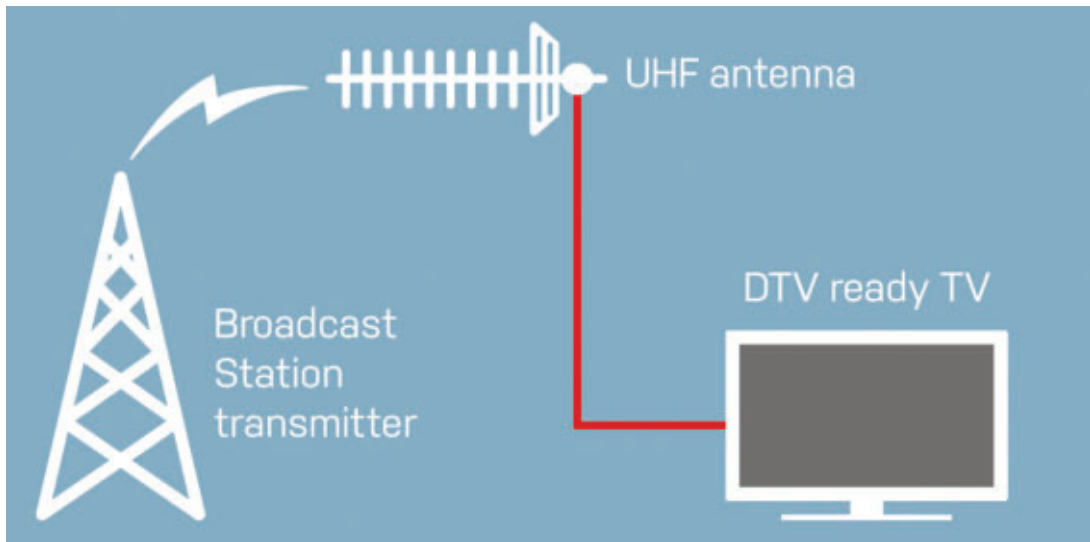
Despite these benefits, the rollout of DTT and D2M in India has been slow and fragmented. Experts recommend phased implementation of DTT, with clear analog switch-off timelines across states and regions, robust encryption technologies, and viewership tracking systems. There is

### डिजिटल टेर्रेस्ट्रियल टेलीविजन (डीटीटी)

**प्रश्न:** डिजिटल टेर्रेस्ट्रियल टेलीविजन (डीटीटी) और डॉयरेक्ट-टू-मोबाइल (डी२एम) का उदय प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को कैसे बदलेगा?

*कृष्णन नायर,  
प्रसारण सलाहकार, चेन्नई*

**उत्तर:** डिजिटल टेर्रेस्ट्रियल टेलीविजन (डीटीटी) एक अधिक कुशल और लचीले प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। हालही में एक घरेलू नवाचार डॉयरेक्ट-टू-मोबाइल (डी२एम) ने ध्यान आकर्षित किया है। डी२एम स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को मोबाइल डेटा या इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर किये बिना लाइव टीवी चैनल और सामग्री देखने की अनुमति देता है, जिससे वफरिंग की समस्यायें समाप्त हो जाती हैं। इन लाभों के बावजूद भारत में डीटीटी और डी२एम का रोलआउट धीमा और खंडित रहा है। विशेषज्ञ राज्यों और क्षेत्रों में स्पष्ट एनालॉग स्विच ऑफ टाइमलाइन, मजबूत एन्क्रिप्शन तकनीक और व्यूरशिप ट्रैकिंग सिस्टम के साथ डीटीटी के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सलाह देते हैं। इस बात पर भी आम सहमति



also growing consensus that private players should be allowed to participate in DTT, currently a Prasar Bharati monopoly, as recommended by TRAI. This would enable consumers to access more channels beyond DD offerings.

The introduction of D2M has raised concerns among Telecom Service Providers (TSPs) and the cable TV industry:

D2M competes directly with TSPs and may not alleviate network congestion, as originally intended.

The free spectrum allocation by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) gives D2M providers an unfair advantage over licensed TSPs and MSOs.

The cable industry, which operates under a strict regulatory and licensing framework, could be adversely impacted.

The 526–582 MHz band, being considered for D2M, holds strong potential for mobile coverage, especially in rural and indoor areas. It is argued that such spectrum should be auctioned fairly, maintaining a “same service, same rules” principle to avoid regulatory arbitrage.

Moreover, critics note that DTT is on the decline globally—being replaced by IPTV, digital cable, and OTT platforms—and question the rationale for reviving it in India, especially given the lack of a seeded decoder market.

Technologies like DTT or D2M offer cost-effective and scalable solutions to reach these underserved “TV-dark” homes—particularly in densely populated and rural areas—for educational content, entertainment, and emergency alerts.

Adopting a hybrid approach, where satellite and terrestrial broadcasting coexist, could maximize coverage and optimize spectrum utilization. Establishing a dedicated national terrestrial broadcast infrastructure, incorporating modern technology and inclusive policies, would help bridge the digital divide and enhance India's media ecosystem. ■



वन रही है कि निजी खिलाड़ियों को डीटीटी में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो वर्तमान में प्रसार भारती का एकाधिकार है, जैसा कि ट्राई ने सुझाया है। इससे उपभोक्ताओं को डीडी की पेशकश से परे और अधिक चैनल तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

डी2एम की शुरुआत ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और केवल टीवी उद्योग के बीच चिंता बढ़ा दी है।

डी2एम सीधे टीएसपी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और मूल रूप से इरादा के अनुसार नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम नहीं कर सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडवी) द्वारा मुफ्त स्पेक्ट्रम आवंटन डी2एम प्रदाताओं को लाइसेंस प्राप्त टीएसपी और एमएसओ पर अनुचित लाभ देता है।

केवल उद्योग जो एक सख्त विनियामक व लाइसेंसिंग के तहत काम करता है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

डी2एम के लिए विचाराधीन 526–582 मेगाहर्ट्ज बैंड में मोबाइल कवरेज के लिए मजबूत हैं, ग्रामीण और इंडोर क्षेत्रों में। इस तरह की स्पेक्ट्रम की नीलामी निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, नियामक मध्यस्थता से बचने के लिए ‘समान सेवा, समान नियम’

सिद्धांत रखना चाहिए।

इसके अलावा, डीटीटी वैश्विकस्तर पर कम होता जा रहा है, इसकी जगह आईपीटीवी, डिजिटल केवल और ओटीटी प्लेटफॉर्म ले रहे हैं और भारत में इसे फिर से शुरू करने के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर सीडेड डिकोडर की मार्केट में कमी को देखते हुए।

डीटीटी या डी2एम जैसी वंचित तकनीकें इन वंचित ‘टीवी डार्क’ घरों तक पहुंचने के लिए लागत प्रभावी और स्केलेबल समाधान प्रदान करती हैं—विशेष रूप से घनी आवादी वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में—शैक्षिक सामग्री, मनोरंजन और आपातकालीन अलर्ट के लिए।

हाइब्रिड दृष्टिकोण को अपनाना, जिसमें सैटेलाइट और स्थलीय प्रसारण एकसाथ हों, कवरेज को अधिकतम कर सकता है और स्पेक्ट्रम उपयोग को अनुकूलित कर सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और समावेशी नीतियों को शामिल करते हुए एक समर्पित स्थलीय प्रसारण अवसंरचना की स्थापना, डिजिटल विभाजन को पाटने और भारत के मीडिया पारिस्थितिकीतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। ■